भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 613**
दिनांक03.02.2026 को उत्तरार्थ

**स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन**

†613. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में अब तक सर्वेक्षण किए गए गांवों और जारी किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या सहित स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जिले के सभी राजस्व गांवों में ड्रोन-आधारित संपत्ति सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है.

(ग) क्या मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से किन्हीं संभार तंत्र या प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या कानूनी, तकनीकी या पट्टा संबंधी मुद्दों के कारण दक्षिण कन्नड़ के कुछ गांव बाहर रह गए हैं और यदि हां, तो ऐसे निष्कासन के कारण क्या हैं और उन्हें कवर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय और समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्तर**

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कुल 422 गांवों में से 81गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है और उन 81 गांवों में 2,605 संपत्ति कार्ड वितरित कर दिए गए हैं।

(ख) स्वमित्व योजना को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) मंत्रालय ने राज्य में ड्रोन उड़ान, जमीनी सत्यता जांचने की प्रक्रिया और संपत्ति कार्ड के वितरण की धीमी प्रगति देखी है।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दक्षिण कन्नड़ जिले के शेष गांवों को स्वामित्व सर्वेक्षण के तहत शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस जिले में ग्रामथाना या सघन आवास बस्तियां नहीं हैं। आवासों का बसावट स्वरूप अत्यधिक बिखरा हुआ है, जो स्वामित्व के आवास स्तर ड्रोन मैपिंग और भूखंड सीमांकन की शर्त को पूरा नहीं करता है।

****